भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 460

19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

**विषय : कृषि पर कमजोर मानसून का प्रभाव**

**460. श्री दयाकर पसुनूरीः**

**डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः**

**श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः**

**श्री एन. रेड्डप्पाः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार का विगत तीन वर्षों के दौरान देश में कमजोर मानसून/कम वर्षा के प्रभाव का आकलन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में राज्य-वार विभिन्न कृषि मदों के उत्पादन तथा किसानों पर ऐसी स्थिति क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) ऐसी स्थिति से निपटने हेतु किसी आकस्मिक योजना को तैयार कर क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) किसानों को भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों और अद्यतन प्रौद्योगिकी से शिक्षित और प्रशिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

**(क) से (घ) :** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षा की कमी के प्रभाव का आकलन किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वर्ष 2016, 2017 तथा 2018 में क्रमश: 3 प्रतिशत, 5 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत की कमी देखी गई थी। देश के विभिन्न भागों में

अवस्थित आईसीएआर संस्थानों द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक तौर पर क्षेत्रीय तथा सिम्यूलेशन अध्ययन किए गए थे।

वर्षा की कमी के कारण पिछले तीन वर्षों (2015-16 तथा 2017-18) के दौरान देश में महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन (ट्रेंड की तुलना) में काफी उतार-चढ़ाव हुए हैं।

एनआईसीआरए के अंतर्गत, सूखा सहय चावल, गेहूं तथा दलहन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एनआईसीआरए की जांचों से कुछ सूखा सहय फसल किस्म जारी की गई हैं। विभिन्न लघु अवधि, उच्च उपज तथा सूखा सहय किस्मों की जांच हो रही है तथा आने वाले वर्षों में उन्हें जारी किया जाएगा।

विलंब से शुरू होने वाले मानसून/वर्षा की कमी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकियों/पद्धतियों का प्रदर्शन किया गया है।

आईसीएआर-सीआरआईडीए तथा अन्य आईसीएआर संस्थानों के साथ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं केवीके ने 650 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं (डीएसीपी) तैयार की हैं और राज्य कृषि विभाग एवं किसान के लिए स्थान-विशिष्ट जलवायु फसलों, किस्मों तथा प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश की है।

राज्य कृषि/बागवानी तथा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा आईसीएआर संस्थानों की सहभागिता से कंसोर्टियम मोड में जिला आधारित कृषि आकस्मिकता योजनाओं को अद्यतन किया जा रहा है।

जलवायु से प्रभावित रहने वाले 151 जिलों में स्थान विशिष्ट जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि किसानों को मौजूदा जलवायु उतार-चढ़ाव से निपटने में समर्थ बनाया जा सके तथा उनकी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाया जा सके। पिछले छ: वर्षों में, जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में किसानों को शिक्षित करने के  लिए एनआईसीआरए परियोजना के अंतर्गत देश भर में 14,407 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था जिसमें 3,72,897 किसान शामिल हुए थे ताकि जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर शुरूआत हो सके तथा उपज में वृद्धि हो सके।

*****